बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 11 अंक 301

लोककल्याण और पूर्वग्रह

गत सप्ताह पेश किए गए अंतरिम बजट के दो प्रावधानों को अत्यंत विपरीत प्रतिक्रियाएं मिली हैं, हालांकि दोनों ही उपाय राजकोषीय विस्तारवाद का उदाहरण हैं। पहली बात, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे किसानों को केंद्र सरकार की ओर से आय समर्थन दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए 6,000 रुपये वार्षिक की जो राशि तय की गई है वह अपेक्षाकृत कम है। यह राशि तीन किस्तों में किसानों के खाते में डाली जाएगी। देश में खेती का रकबा इतना बंटा हुआ है कि सैद्धांतिक रूप से इस योजना से बहुत बड़ी तादाद में लोग लाभान्वित होंगे। वित्त मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक इससे करीब 12 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा। यह देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। बजट के मुताबिक अगले वर्ष इस योजना के चलते 75,000 करोड़ रुपये की राशि व्यय करनी होगी। एक अन्य निर्णय जिसने सुर्खियां बटोरीं वह कर राहत के रूप में लिया गया। इसके तहत सालाना 5 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को कर में छूट प्रदान की गई है। कर नियमों में थोड़े बहुत बदलाव के साथ यह खजाने पर 23,000 करोड़ रुपये का बोझ डालने वाली योजना है।

यह खेद की बात है कि सार्वजनिक बहस में इन दोनों नीतिगत निर्णयों को लेकर होने वाली बहस काफी बंटी हुई है। ऐसे समय में जबकि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उस वक्त कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किए जाने की आलोचना करना एक बात है। लेकिन इसके बावजूद कर कटौती का स्वागत किया जाना कतई उचित नहीं है।

इसके साथ ही साथ देश के सबसे हाशिये पर मौजूद किसानों के लिए न्यूनतम आय समर्थन की आलोचना करना भी बिल्कुल विचित्र है। देश की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 31 जनवरी, 2019 को जारी किए गए शुद्ध राष्ट्रीय आय के प्रथम संशोधित आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 के लिए यह लगभग 1.1 लाख रुपये सालाना रही। दूसरे शब्दों में कहें तो 5 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को कर मुक्त करने का अर्थ यह है कि न्यूनतम आय से पांच गुना तक आय अर्जित करने वालों को भी अब आय कर चुकाने की आवश्यकता नहीं है।

यह अस्वाभाविक स्थिति है। अगर प्रति व्यक्ति आय शक्ति के हिसाब से आकलन किया जाए तो भी तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। 12,500 रुपये की कर राहत के हिसाब से देखा जाए तो देश के सबसे सीमांत किसानों को 6,000 रुपये प्रति परिवार की राहत बहुत अधिक नहीं है। इससे करीब 12 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा जबकि आयकर में छूट का लाभ अधिकतम 3 करोड़ लोगों तक ही पहुंचेगा। इसमें बहुत कम संदेह है कि प्राथमिकता किसे प्रदान की जाए। आय के अनुरूप कराधान अथवा आय के पुनर्वितरण के सवालों को तो अभी छोड़ ही देते हैं।

मध्य वर्ग के विस्तारित पूर्वग्रह के साथ समस्या यह है कि कई बार इसका आकलन तथ्यात्मकता से दूर हो जाता है। यह बात अहम है कि कल्याणकारी उपायों तक के राजकोषीय तथा अन्य लाभों का आकलन अधिकतम निष्पक्ष होकर किया जाए। इस मामले में कर में कटौती की तुलना अगर किसानों को दिए गए आय समर्थन से की जाए तो वह एक राजकोषीय विलासिता है। किसानों को दी गई राहत को ग्रामीण संकट और आय की दिक्कत को दूर करने का न्यूनतम उपाय माना जा सकता है। चाहे जो भी हो लेकिन इन दोनों उपायों के प्रति प्रतिक्रिया में एक का स्वागत और दूसरे को लेकर निराशा को पाखंड मानकर खारिज कर दिया जाना चाहिए।

बिनय सिन्हा

भारतीय बैंकिंग के क्षेत्र में तीन दिलचस्प विलय

जयकुमार और वैद्यनाथन भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े हैं जबकि घोष के लिए एक बाध्यता है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं **तमाल बंद्योपाध्याय**

पी एस जयकुमार, वी वैद्यनाथन और चंद्र शेखर घोष इन तीनों के साथ एक खास बात क्या है? ये तीनों ही भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में तीन सर्वाधिक दिलचस्प विलय प्रक्रिया को अंजाम देने में जुटे हैं। घोष के नेतृत्व वाले बंधन बैंक ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैंस कॉर्प लिमिटेड (एचडीएफसी) की सहायक इकाई गृह फाइनैंस लिमिटेड का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। इसी तरह, वैद्यनाथन की कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड का आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो चुका है। एक अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम में दो अपेक्षाकृत छोटे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों- देना बैंक और विजय बैंक- का जयकुमार के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) में विलय हो रहा है। जयकुमार और वैद्यनाथन दोनों ही इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े हैं। वजह भी साफ है, क्योंकि इन दोनों को जिस कार्य की जिम्मेदारी दी गई है, उसकी मिसाल भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में पहले देखने को नहीं मिली थी। बीओबी-देना-विजय बैंक का आपस में विलय भारत के सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र में समेकन का पहला उदाहरण है।

ऋण परिसंपत्तियों में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी लगभग 70 प्रतिशत के करीब है। हालांकि इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पांच सहायक बैंकों का विलय हो चुका है, लेकिन यह एक आंतरिक मामला था। वैसे इस विलय से देश का सबसे बड़ा कर्जदाता एसबीआई विश्व के शीर्ष 50 बैंकों की फेहरिस्त में शामिल हो गया था। इसी तरह, आईसीआईसीआई बैंक के सबसे युवा कार्यकारी निदेशक वैद्यनाथन, जिन्होंने एक उद्यमी बनने का निर्णय लिया, पहले ऐसे पेशेवर हैं जिन्हें बिना आवेदन किए ही बैंकिंग लाइसेंस मिल गया! सभी व्यावहारिक कारणों से उनकी गैर-वित्तीय बैंकिंग कंपनी कैपिटल फर्स्ट आईडीएफसी बैंक का अधिग्रहण कर रहे हैं। आईडीएफसी बैंक को अस्तित्व में आए उतना ही समय हुआ है, जितना बंधन बैंक को हुआ है। ये तीनों लोग निवेशकों की अपेक्षाओं को साधने में लगे हैं, लेकिन मैं उस पहलू पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। इसका कारण यह है कि सभी विलय पहले ही दिन से गुणवत्ता का समागम करेंगे ऐसा भी नहीं है, लेकिन शेयरधारकों को दीर्घ अवधि में जाकर इसका लाभ मिल सकता है। सेंचुरियन-बैंक ऑफ पंजाब का एचडीएफसी बैंक के साथ विलय इसका एक उदाहरण है।

बैंकिंग क्षेत्र में समेकन की प्रक्रिया स्पष्ट तौर पर दिख रही है, लेकिन बीओबी के साथ देना बैंक और विजय बैंक के विलय में देना बैंक को उबारने का भी उद्देश्य निहित है। देना बैंक को तथाकथित सुधार सूची (प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन/पीसीए) में डाल दिया गया है और इसकी सामान्य बैंकिंग गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई है। दिसंबर, 2015 में बैंकिंग के फंसे कर्ज का आंकड़ों में इजाफा शुरू होने के बाद देना बैंक को सितंबर 2018 तक 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। बैंक को इस दौरान 12 तिमाहियों में 11 में नुकसान उठाना पड़ा। इस अवधि के दौरान बैंक की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 9.85 प्रतिशत से बढ़कर 23.64 प्रतिशत हो गईं। सरकार नियंत्रित बैंकों में यह एनपीए का चौथा सबसे बड़ा आंकड़ा था।

जयकुमार ने बीओबी का बहीखाता दुरस्त करने और इसके परिचालन में उपयुक्त बदलाव लाने के लिए कई पहल किए हैं, लेकिन विलय एक अलग ही मामला है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती देना बैंक और विजय बैंक के वरिष्ठ कर्मचारियों की चिंताओं को साधने की होगी। इसमें कोई शक नहीं कि इन वरिष्ठ कर्मचारियों के मन में उनके साथ अनुचित भेदभाव होने का भय सताता रहेगा। अगर देना बैंक का बहीखाता जितना कमजोर दिख रहा है उससे भी कमजोर दिखा तो यह मनोभावना और बिगड़ सकती है। याद करें कि किस तरह सहायक बैंकों के समागम के बाद एसबीआई का फंसा कर्ज सरपट ऊपर भागा था। विलय के बाद अस्तित्व में आने वाली नई इकाई एसबीआई और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी कर्जदाता होगी। इस इकाई की 9,489 शाखाओं में 85,675 लोग काम करेंगे।

आईडीएफसी बैंक, जो शेयरधारकों की अनुमति के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो जाएगा, का बहीखाता 1.03 लाख करोड़ रुपये होगा। यह अपनी 203 शाखाओं और 454 ग्रामीण बैंकिंग प्रतिनिधि केंद्रों के जरिये अपने 72 लाख ग्राहकों को सेवाएं मुहैया कराएगा। कुल ऋण खाते में इसका खुदरा ऋण खाता 32.46 प्रतिशत का योगदान देगा। बहीखाता में वृद्धि करने और तकनीक को तवज्जो देने के लिए खास तौर पर मशहूर वैद्यनाथन ने बैंक में ऊपरी स्तर पर फेरबदल भी किए हैं। कैपिटल फर्स्ट से बैंक के खुदरा कारोबार को मजबूती मिलेगी, वहीं वैद्यनाथन के लिए सबसे बड़ी चुनौती कम लागत वाली देनदारी के साथ आगे बढ़ने की होगी। इन दोनों इकाइयों को छोड़ दें तो बंधन बैंक के लिए गृह फाइनैंस का सौदा एक मजबूरी है। बंधन बैंक देश में किसी सूक्ष्म वित्त इकाई के बैंक में तब्दील होने का पहला उदाहरण है। आरबीआई के लाइसेंस संबंधी नियमों के तहत परिचालन शुरू करने के तीन साल के भीतर इकाई को सूचीबद्ध कराना जरूरी है और प्रवर्तकों को हिस्सेदारी कम कर 40 प्रतिशत करना अनिवार्य है। बंधन बैंक की शुरुआत 23 अगस्त, 2015 को हुई थी और यह सूचीबद्ध भी हो गई है, लेकिन प्रवर्तकों की हिस्सेदारी जरूरी स्तर तक नहीं आई है। गृह फाइनैंस के अधिग्रहण के बाद प्रवर्तकों को उनकी हिस्सेदारी कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी। ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि बंधन बैंक और गृह फाइनैंस का सौदा दोनों ही इकाइयों के अल्पांश शेयरधारकों के लिए अच्छा नहीं है और वास्तविक लाभ एचडीएफसी को मिलेगा। एचडीएफसी के पास गृह फाइनैंस की बहुलांश हिस्सेदारी है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सौदा बंधन के लिए ठीक है, लेकिन बैंक को इसके लिए अधिक भुगतान करना पड़ रहा है।

विलय प्रक्रिया पूरी होने के बाद बंधन बैंक का ऋण खाता बढ़कर 50,000 करोड़ रुपये (सितंबर 2018 की कमाई के आधार पर) हो जाएगा और यह अपने 1.5 करोड़ ग्राहकों को 4,182 बैंक शाखाओं से सेवाएं देगा। गृह फाइनैंस का आधा से अधिक कारोबार ग्रामीण क्षेत्रों में होता है और इसका औसत ऋण आकार 9.4 लाख रुपये है। पश्चिमी और मध्य भारत में इसकी उपस्थिति से बंधन बैंक को कारोबार बढ़ाने में खासी मदद मिलेगी। विलय से बंधन बैंक को पोर्टफोलियों संकेंद्रण से जुड़े जोखिम कम करने, कारोबार में विविधता लाने और गृह फाइनैंस की योजनाएं बेचने में भी मदद मिलेगी। हालांकि घोष के सामने कार्य करने की शैली से जुड़ी विविधताओं के साथ सामंजस बैठाने की चुनौती होगी। गृह फाइनैंस तकनीक पर अधिक जोर देती है और इसके वरिष्ठ अधिकारी बैंक के अपने समकक्षों के मुकाबले अधिक तवज्जो पाते हैं। हालांकि घोष ने बैंक की शुरुआत करने के समय नव नियुक्त बैंकरों और अपने सूक्ष्म-वित्त कर्मचारियों को बराबर तवज्जो देने में अच्छी भूमिका निभाई थी। (डिस्क्लेमर: मैं बतौर सलाहकार, रणनीति, इस बैंक के साथ अगस्त 2015 से अक्टूबर 2018 तक जुड़ा रहा)

राकेश शर्मा के सामने भी चुनौती कम नहीं है। फंसी परिसंपत्तियों के मामले में आईडीबीआई बैंक देना बैंक को टक्कर दे सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) आईडीबीआई बैंक का अधिग्रहण कर रहा है, जो एक बार फिर भारतीय बैंकिंग जगत में एक अनूठा प्रयोग है। शर्मा निजी क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले उन दो मुख्य कार्याधिकारियों (सीईओ) में शामिल थे (दूसरे जयकुमार थे), जिन्हें एक सरकार नियंत्रित बैंक संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि एलआईसी के अधिग्रहण की कवायद देखने के लिए मात्र छह महीने का कार्यकाल दिया गया है। जयकुमार करीब एक साल तक रहेंगे। लिहाजा, दोनों हड़बड़ी में हैं, लेकिन वैद्यनाथन और घोष के पास हालात संभालने के लिए खासा समय है।

(स्तंभकार लेखक और जन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड में वरिष्ठ सलाहकार हैं। वह बिज़नेस स्टैंडर्ड के सलाहकार संपादक हैं।)

असल आंकड़ों को छुपा रही केंद्र की मोदी सरकार

नीति नियम

मिहिर शर्मा

दुर्भाग्य से अब यह व्यापक रूप से माना जाने लगा है कि हम भारत सरकार के आंकड़ों पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं यहां सकल घरेलू उत्पाद की गणना की 'नई शृंखला' को लेकर बात नहीं कर रहा। ना ही मैं इसी जीडीपी की भरोसे न करने लायक 'बैक सीरीज' की बात कर रहा हूं। मैं ईपीएफओ के आंकड़ों का इस्तेमाल कर रोजगार वृद्धि के किए गए दावों के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां बजट में पेश सबसे अहम वृहद आर्थिक संकेतकों के बारे में बात कर रहा हूं।

अंतरिम बजट के आंकड़ों को लेकर यह नहीं कहा जा सकता कि ये हकीकत को ठीक से बयां करते हैं। सरकार ने सभी परंपराओं की उपेक्षा की है और पूर्ण बजट पेश किया है। बजट में यह दावा किया गया है कि भारत लगातार 'राजकोषीय सुदृढ़ता की राह' पर चल रहा है और घाटा जीडीपी का 3 फीसदी रहेगा। इस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के अंतिम वर्ष समेत 2013 के संकट के बाद शुरुआती कुछ वर्षों में घाटे को कम करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास किए गए। लेकिन ऐसा लगता है कि अब वे प्रयास बंद हो गए हैं। इस साल कोई प्रमुख वृहद आर्थिक संकट नहीं होने के बावजूद राजकोषीय घाटे का लक्ष्य फिर हासिल नहीं हो पाया। यह उन वर्षों की याद दिलाता है, जब संप्रग सरकार के वरिष्ठ अधिकारी लगातार ये दावे करते थे कि 8 फीसदी वृद्धि केवल 2-3 तिमाही दूर है।

बजट की बातें उसी तरह अविश्वसनीय हैं। इसका कोई सही जवाब नहीं दिया गया है कि वस्तु एवं सेवा कर की प्राप्तियां बजट अनुमान से 1 लाख करोड़ कम क्यों हैं। ये इस साल करीब 6 फीसदी बढ़ेंगी। ऐसे में हमें बजट का यह दावा क्यों मानना चाहिए कि वे अगले साल करीब 20 फीसदी बढ़ेंगी? अगर वे नहीं बढ़ीं तो बजट के अनुमानों का क्या होगा?

राजकोषीय स्थिति को नियंत्रित रखने का बहुत बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। हालांकि अब तक के सबूत यह दर्शाते हैं कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि वह इसका श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन खर्च को नियंत्रित रखने या राजस्व बढ़ाने के अनिच्छुक नजर आते हैं।

मोदी सरकार खर्च को नियंत्रित नहीं करना चाहती है, जिसके नतीजतन बजट घाटे का आंकड़ा अवास्तविक अनुमानों के कारण न केवल अविश्वसनीय है, बल्कि पूरी तरह भ्रामक भी है। सरकारी खर्च को सरकार के नियंत्रण में आने वाली अन्य नकदी से वित्त पोषित कर छिपाया जा रहा है।

एयर इंडिया को उबारने के लिए लघु बचत कोष का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले यह काम बजट आवंटन के जरिये किया जाता था। यह सरकार का कर राजस्व नहीं है, जिसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये हमारी बचत हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि की धनराशि। इसका इस्तेमाल एयर इंडिया को बचाने जैसी राजनीतिक जरूरतों के लिए किया जा रहा है। लेकिन किसी की बचत का गर्दिश में जा रही उस विमानन कंपनी में निवेश होना बहुत ही बेकार है। इसमें करों से आने वाला पैसा खर्च किया जाना चाहिए। हम संकटग्रस्त किंगफिशर को ऋण देने को लेकर बैंकरों की आलोचना क्यों करते हैं, जब हमारी बचत की संरक्षक सरकार भी एयर इंडिया के मामले में ठीक वही कर रही है।

विनिवेश का भी दुरुपयोग हो रहा है। अब इसका मतलब सरकारी नियंत्रण में कमी और इस तरह सरकारी क्षेत्र में लगी पूंजी की उत्पादकता में बढ़ोतरी नहीं रह गया है। इसके बजाय विनिवेश सार्वजनिक क्षेत्र से सरकार को पूंजी हस्तांतरित करना बन गया है। फिर सरकार इसका इस्तेमाल खर्च के वित्त पोषण में करती है। यह सार्वजनिक संसाधनों का बेजा दुरुपयोग है। इससे लगातार अर्थव्यवस्था में अकुशलता और पूंजी के गलत आवंटन में बढ़ोतरी हो रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की जिन कंपनियों को अपना आरक्षित कोष निवेश के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें वह पैसा सरकार को देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। सरकार की प्रमुख नीतियां पूरी करने के लिए सार्वजनिक एजेंसियों को कर्ज लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

बजट में राजमार्ग मंत्रालय का आवंटन घटा दिया गया है। अगले साल के लिए बजट चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में केवल 6 फीसदी बढ़ाया गया है। इसके नतीजतन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जैसी एजेंसियां सरकारी ऑर्डरों के लिए उधारी बढ़ा रही हैं। हालांकि बजट के आंकड़ों मे इसे नहीं दिखाया जा रहा है।

एनएचएआई पर 1.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है और उसकी आमदनी या नकदी प्रवाह नगण्य है। यह सरकारी गारंटी पर नए कर्ज लेकर अपने पुराने कर्ज चुका रहा है। यह जिन सड़कों पर कर्ज लेता है, वे उसकी नहीं बल्कि सरकार की संपत्ति हैं। आगे एनएचएआई के बाजार से 60,000 करोड़ रुपये और भारतीय खाद्य निगम के 1 लाख करोड़ रुपये जुटाने का अनुमान है। इस उधारी का निर्देश और गारंटी सरकार देती है, लेकिन यह बजट में नहीं दिखती है। इन सबका एक संभावित निष्कर्ष यह है कि मोदी राजकोषीय मितव्ययी होने का श्रेय पाने के हकदार नहीं हैं। असल में वह खर्चीले साबित हुए हैं। अगर निजी निवेश नहीं सुधरा तो इसकी वजह यह है कि सरकार ने बाजार को अपने बॉन्डों से पाट रखा है। सरकार को अपना खर्च करों से चलाना चाहिए।

आपको जीडीपी के आंकड़ों पर हंसी आ सकती है, जिनमें दावा किया गया है कि हम नोटबंदी के वर्ष में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़े। लेकिन यदि आप जीडीपी के आंकड़ों में भरोसा रखते हैं तो आपको गौर करना चाहिए कि पिछले साल जीडीपी में भारी गिरावट आई है, जबकि उस दौरान उधारी में बढ़ोतरी हुई है। मोदी का बड़ा दांव नाकाम रहा है। उनका दांव था कि जब सरकारी खर्च को बड़ी बातों और छोटे सुधारों के साथ मिला दिया जाएगा तो निवेश शुरू हो सकता है। उन्होंने सुधरती अर्थव्यवस्था अपने हाथ में ली थी, लेकिन उन्होंने इसे जमीन पर ला दिया।

कानाफूसी

अंत में प्रार्थना...

संकट से जूझ रहे ज़ी समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने पिछले सप्ताह निवेशकों से आग्रह किया कि वे ज़ी समूह और डिश टीवी के शेयर खरीदकर 'नकारात्मक ताकतों' को पराजित करने में सहायता करें। उन्होंने यह अपील तब की जब समूह की कंपनियों के शेयरों में तेजी से गिरावट आने लगी। उनकी इस अपील पर लोगों की दृष्टि पड़नी लाजिमी थी क्योंकि आमतौर पर कंपनियों के प्रवर्तक अपनी कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए ऐसी अपील नहीं करते। एक विश्लेषक ने कहा कि ज़ी समूह के मुखिया को लोगों से शेयर खरीदने की अपील करने के बजाय ट्राई की नई नीति के कारण उपजी अनिश्चितता के बीच दर्शकों से यह मांग करनी चाहिए थी कि वे कम से कम कंपनी के चैनलों को अधिक संख्या में सबस्क्राइब करें। दरअसल नए दिशानिर्देश आने के बाद पारदर्शिता बढ़ी है और उपभोक्ता अपनी पसंद के चैनल सबस्क्राइब करने के लिए भी स्वतंत्र हैं।

नायडू की अगुआई

ऐसा प्रतीत होता है कि तेलुगू देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने महागठबंधन के बचाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच के मतभेद दूर करने के लिए आगे आने का निर्णय किया है। पिछले दिनों वह दिल्ली आए थे और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का एक साथ आना लोकतांत्रिक अनिवार्यता हो चुकी है, हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए साझा समूह खड़ा करते हुए भी राज्य स्तर पर विभिन्न दलों की राजनीतिक अनिवार्यताओं का ध्यान रखना होगा। उनका यह वक्तव्य मायने रखता है क्योंकि आप और कांग्रेस के बीच अभी गठबंधन होना है। दोनों दल लगातार एक दूसरे को लेकर आक्रामक भूमिका में नजर आए हैं। दोनों लगातार यह कह रहे हैं कि वे आगामी चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे।

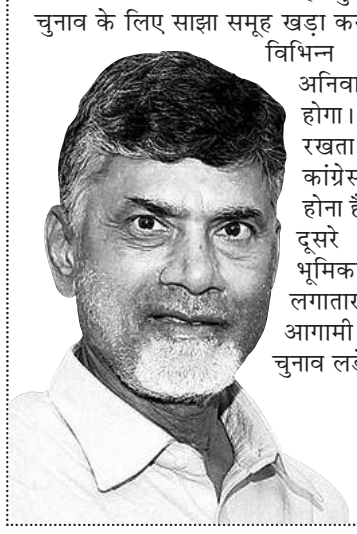

आपका पक्ष

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाएं मजबूत

भारत में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखने की जरूरत है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस क्षेत्र में सुधार करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। जब ग्रामीण स्तर पर रोजगार उपलब्ध होंगे तभी इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है। इसके लिए कृषि से जुड़े विभिन्न घरेलू उद्योगों जैसे अचार, मुरब्बा, अगरबत्ती उद्योग, दाल, चिप्स आदि का प्रशिक्षण मुफ्त में दिया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि आधारभूत जरूरतों की पूर्ति की जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष 50-70 लाख रोजगार उत्पन्न करने की जरूरत है, जो सिर्फ सरकारी क्षेत्र में संभव नही हैं। इसलिए विभिन्न क्षेत्रो में रोजगार पैदा करने के लिए कौशल विकसित करने की जरूरत है। देश के 90 प्रतिशत से अधिक कामकाजी लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में ना तो रोजगार सुरक्षित है और ना ही

किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा है। हमें ये दोनों सुविधाएं देने की जरूरत है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में भी कई समस्याएं हैं। यहां सिर्फ साक्षरता पर ध्यान दिया जाता है, व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा पर नहीं। इस व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। साथ ही, जनसंख्या पर नियंत्रण करने की जरूरत है जिससे संसाधनों पर

केंद्र सरकार को बेरोजगारी दूर करने के लिए कौशल विकास पर अधिक जोर देना चाहिए

अत्यधिक भार ना पड़े। सरकारी योजनाओं का भी सही ढंग से क्रियान्वयन तथा भ्रष्टाचार मिटाकर पारदर्शिता लाने की जरूरत है।

संगीता चौधरी, जयपुर

ऑनलाइन जालसाजी से रहें सावधान

आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले बहुत अधिक चर्चा में आ रहे हैं। डिजिटल लेनदेन पर साइबर हमले का खतरा, एटीएम टेंपरिंग और एटीएम कार्ड की क्लोनिंग जैसी घटनाएं बढ़ गई हैं। वित्तीय संस्थानों ने अपने एटीएम में सुरक्षा को बढ़ाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए कई रणनीतियां लागू की हैं। इनमें एटीएम स्थापना के लिए सुरक्षित स्थान का चयन, कैमरों की स्थापना और उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाना आदि उपाय शामिल हैं। हालांकि हमें एटीएम का उपयोग करते समय लगातार सावधानी बरतनी होगी। हमें आसपास घूम रहे किसी भी संदिग्ध की जानकारी तत्काल बैंक को देनी चाहिए। साथ ही, अपना एटीएम कार्ड और पासवर्ड किसी भी व्यक्ति से साझा नहीं करना चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग के तहत लेनदेन करते समय सुरक्षित वेब ब्राउजर का ही इस्तेमाल करना चाहिए और कंप्यूटर या लैपटॉप को पासवर्ड फ्री रखना चाहिए।

पल्लवी शर्मा, लखनऊ

ठोस पहल की जरूरत

आज हमारा देश बेरोजगारी के बड़े संकट से जूझ रहा है। अगर सरकार वास्तव में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना चाहती है तो उसे दो सकारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे। पहले कदम के तहत सरकार को नीति बनाकर पूरे देश में समान काम, समान वेतन का नियम लागू करना चाहिए। दूसरा, सरकार पूरे देश में एक न्यूनतम वेतन को लागू करे। इसके जरिये सबसे गरीब आदमी को भी महंगाई से लड़ाई लड़ने में सहायता मिलेगी। अगर सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कदम नहीं उठाए तो आगे चलकर स्थिति भयावह हो सकती है।

दौलत राम, श्रीगंगानगर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।